

The number of experts required at each plant are determined on a year to year basis. The tenure of individual experts are determined by the Soviet Organisations. Their present terms and conditions include entitlement to:

Transfer Grants.

Air passage for the specialist and his family.

Leave on full pay at the rate of one day for every 11 days, if a Specialist works in India.

Free medical attendance and treatment for the Specialist and his family.

Free transport to the site of work and back; and Insurance.

सरकारी क्षेत्र के घाटे में कमी

1354. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के घाटे को कम करने के लिए उनके उत्पादों की कीमतें समय-समय पर बढ़ाई जाती हैं जिससे अन्ततः अन्य वस्तुओं की कीमतों पर प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से सरकारी क्षेत्र के उद्योग घाटे में चल रहे हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन वस्तुओं की कीमतों में कितनी बार वृद्धि की गई ; और

(ग) क्या इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये कोई उपाय किये गये हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) यह अनुमान है कि माननीय सदस्य का आशय महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र जैसे इस्पात, कोयला आदि के बारे में नियंत्रित मूल्यों/मूल्य वृद्धि से है, जिसके लिये सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। अतः इनके लिये सरकार द्वारा स्वीकृत मूल्य-वृद्धि मुख्यतः काम में आने वाली सामग्री की बढ़ी हुई लागत की प्रतिपूर्ति

करना है, न कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में घाटे को कम करना।

(ख) और (ग) उपर्युक्त "क" के उत्तर को देखते हुये (ख) और (ग) के प्रश्न ही पैदा नहीं होते। किन्तु, 1983-84 में जिन उद्यमों ने घाटा उठाया है, उनके नाम लोक उद्यम सर्वेक्षण के खंड-1 में पृष्ठ 61 से 63 पर उपलब्ध हैं जिसे 15 मार्च, 1985 को राज्य सभा-पटल पर रखा गया था।

इसी प्रकार, 31 मार्च, 1984 को समाप्त तीन वर्ष के दौरान काम में आने वाली आधारभूत सामग्री जैसे इस्पात, कोयला आदि में हुई मूल्य-वृद्धि का विवरण लोक उद्यम सर्वेक्षण 1983-84, 1982-83 और 1981-82 के खंड-1 में "सरकारी उद्यमों में मूल्य-निर्धारण नीति संबंधी" अध्याय में उपलब्ध है।

"किमिनल बैंकिंग" शीर्षक के अन्तर्गत सम्पादकीय

1355. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 फरवरी, 1985 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित "किमिनल बैंकिंग" शीर्षक के अधीन प्रकाशित सम्पादकीय की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि विभिन्न राष्ट्रीय-कृत बैंकों के कार्यों में अनियमितताओं के लिये अध्यक्ष और प्रबंधक को दोषी पाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।